डी.ओ. सं. ए-42011/1/2013-समन्वय

जनवरी, 2014

प्रिय महोदय,

शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में दिसंबर, 2013 हेतु महत्वपूर्ण नीति निर्णयों/घटनाओं का मासिक सार निम्न प्रकार हैः-

1. **महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामलेः**

- सचिव (शहरी विकास) के नेतृत्व में शहरी विकास मंत्रालय के एक शिष्टमंडल ने दूसरें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम तथा तीसरें फ्रेन्डशिप सिटीस और स्थानीय शासन सहयोग फोरम में हिस्सा लिया जो डर्बन, दक्षिण अमेरिका में 27 से 29 नवंबर, 2013 के बीच आयोजित था।

- एनबीसीसी द्वारा निर्मित किए जाने वाले राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नैटग्रिड) के डाटा केन्द्रों का भूमिपूजन नई दिल्ली में माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार, श्री सुशील कुमार शिंदे के कर कमलों से किया गया।

- एनबीसीसी को 6 प्राथमिक डाटा केन्द्र बनाने का कार्य सौंपा गया है और इसी आकार के बीसीपी डाटा केन्द्र, दिल्ली तथा आपदा स्वास्थ्य लाभ केन्द्र, बेंगलुरु में भी निर्मित किए जाएंगे। नैटग्रिड परियोजना आसूचना अभिकरणों के डाटाबेस और सूचना प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच कड़ी की परिकल्पना करता है जिससे की आतंकरोधी क्षमताओं में वृद्धि की जा सके।

2. **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के एक घटक शहरी अधोसंरचना और अभिशासन (यूआईजी) के अंतर्गत कार्रवाई के प्रमुख बिन्दुः**

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहर विकास योजनाओं (सीडीपी), समझौता ज्ञापन (एमओए), और केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक के संबंध में प्रगति रिपोर्ट **अनुलग्नक-I** में रखी गई है।

3. कैबिनेट/कैबिनेट समिति के निर्णयों पर कार्यान्वयन के विवरणों को पृथक तौर पर भेजा जा रहा है।

जारी......

4. अन्य क्षेत्रों अर्थात क्र.सं. (iii) और (v) जिसे कैबिनेट सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1/81/19/2007-सीए.IV दिनांक 24.09.2007 में इंगित के संबंध में प्रतिवेदन करने हेतु कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।

सादर,

भवदीय,

(सुधीर कृष्णा)

संलग्नकः उपरोक्त

श्री ए.के. सेठ,
कैबिनेट सचिव,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः-

1. श्री पुलोक चटर्जी,
   प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव,
   साउथ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव,
3. राज्यमंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव।
4. एनआईसी (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

(सुधीर कृष्णा)

<u>अनुलग्नक-I</u>

दिसंबर, 2013 हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत हुई प्रगति

मद	नवंबर, 2013 तक स्थिति	दिसंबर, 2013 के दौरान स्थिति	अब तक की स्थिति
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठकें (31/03/2012 तक अनुमोदित जारी परियोजनाएं)			
i. आयोजित बैठकों की संख्या	128	1	129*
ii. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	572(539)	0	572(539)**
iii.संपन्न परियोजनाओं की संख्या	218	0	218
iv.वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।	20,062.64 करोड़ रुपए	182.55 रुपए	20,245.19 करोड़ रुपए
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठकें (मार्च 2013 से ट्रांजिशन फेस)			
v. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या vi.वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।	28 142.48 करोड़ रुपए	17 12.54	45 155.02 करोड़ रुपए
सकल योग			
vii. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	600(567)	17	617(584)
viii. वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।	20,205.12 करोड़ रुपए	195.09 रुपए	20,400.21 करोड़ रुपए

* दिनांक 04/06/07, 13/06/07 एवं 02/06/10 को आयोजित तीन विशेष सीएसएमसी बैठकों को मिलाकर

** अब तक कुल 617 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है (दिनांक 29/09/07 को आयोजित सीएसएमसी की 56वीं बैठक में एक परियोजना को वापस ले लिया गया)। दो परियोजनाओं को सीएसएमसी की दिनांक 22/01/10 को आयोजित 81वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 05/03/10 को आयोजित सीएसएमसी की 83वीं बैठक में एक परियोजना को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 21/05/10 को आयोजित 86वीं बैठक में वापस ले लिया गया।

दो परियोजनाओं को सीएसएमसी की दिनांक 20/08/2010 को आयोजित 89वीं बैठक में

वापस ले लिया गया। दिनांक 12/11/2010 को आयोजित सीएसएमसी की 91वीं बैठक में पांच परियोजनाओं को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 17/08/2011 को आयोजित 93वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 12/04/2012 को आयोजित बैठक में दिल्ली की पांच परियोजनाओं को जीएनसीटीडी द्वारा छोड़ दिया गया। दिनांक 12/07/2012 को आयोजित सीएसएमसी की 110वीं बैठक में पश्चिम बंगाल की दो परियोजनाओं को राज्य द्वारा छोड़ दिया गया। दिनांक 26/12/2012 को आयोजित सीएसएमसी की 115वीं बैठक में गुजरात की एक परियोजना को राज्य द्वारा छोड़ दिया गया। सीएसएमसी की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 30/10/2012 को आयोजित 113वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 04/09/2013 को आयोजित सीएसएमसी की 125वीं बैठक में 10 परियोजनाओं को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 16/09/2013 को आयोजित 126वीं बैठक में वापस ले लिया गया। इस प्रकार कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या 584 है; जिसमें 45 नई परियोजनाएं शामिल है जिन्हें ट्रांजिशन फेस के दौरान 119वीं सीएसएमसी से 129वीं सीएसएमसी के बीच स्वीकृत किया गया है।

<u>*******</u>

अनुलग्नक II:

मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसंबर, 2013 तक का कार्यप्रदर्शन

कार्यक्रम	कैबिनेट अनुमोदन	कार्यान्वन की अवधि	कुल परिव्यय (रु. करोड़ में)	बजट 2013-14	लक्ष्य	उपलब्धि
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)					कार्यों का कार्यान्वयन वित्तांश-II का कार्यान्वयन	**वित्तांश - I परियोजनाएं** आईजॉल जल आपूर्ति हेतु निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शिलाँग, कोहिमा, अगरतला और सिक्किम में अन्य परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2015 में पूर्ण करना निर्धारित किया गया है। **वित्तांश-II** 1. अगरतलाः 8 ठेके प्रदान किए गए हैं; तकनीकी मूल्यांकन, के अंतर्गत 1 पैकेज। 2. आईजॉल परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। 3. गंगटोकः 5 पैकेजेस प्रदान किए गए हैं। वित्तीय मूल्यांकन के अंतर्गत 5 पैकेजेस। 4. कोहिमा-1 ठेका प्रदान किया गया। बाद में 1 पैकेज जारी किया जाएगा। 5. शिलाँग-2 ठेका प्रदान किया गया। 1 बोली दिए जाने के लिए तैयार है। एलओए जारी किया गया।

कार्यक्रम	कैबिनेट अनुमोदन	कार्यान्वयन की अवधि	कुल परिव्यय (रु. करोड़ में)	बजट 2013-14	लक्ष्य	उपलब्धि
शहरी विकास और लोक निर्माण से संबंधित मामलों पर सहयोग हेतु दक्षिण अफ्रिका गणतंत्र सरकार और भारत सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया।	24/01/2012	6 महीने के भीतर	-	-	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	परस्पर सुविधाजनक तिथि और स्थान के चयन को अंतिम रूप देने के लिए विचार किया जा रहा है।
निर्माण विकास क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति की समीक्षा	28/11/2013	वित्त मंत्री महोदय के साथ मामले पर चर्चा करने और इस हेतु बैठक आयोजित करने के अनुरोध के साथ माननीय शहरी विकास मंत्री को पत्रावली प्रस्तुत की गई है।				
सात मेगा शहरों के सैटेलाइट टाउन्स में अधोसंरचना विकास हेतु योजना (यूआईडीएसएसटी)	जुलाई, 2009	2009-17	500	रु. 78.00 करोड़	चालू परियोज-नाओं के लिए फंड जारी	योजना के अंतर्गत, 17 परियोजनाएं प्रगति पर है, वसई विरार, सोनीपत, विकाराबाद, पिल्खुआ, सानंद, श्रीपेरम्बदुर और होस्कोटे नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और भूमिगत सिवेज योजना प्रगति पर है। कुल वित्तीय परिव्यय रु. 500 करोड़ में से रु. 229.67 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है और स्थायी देयताएं रु. 270.32 करोड़ की हैं।